Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Multidisciplinary Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 8.054,
January to March 2025 E-Journal, Volume I, Issue XLIX, ISO 9001:2015 - E2024049304 (QMS)

कृषि आधारित उद्योग और ग्रामीण विकास का सुक्ष्म भौगोलिक अध्ययन

अनिल कुमार यादव* डॉ. ए.के. सिंह**

* शोध छात्र (भूगोल) एस.एल.पी. स्नातकोत्तर महाविद्यायल, मुरार, ग्वालियर (म.प्र.) भारत
** प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष (भूगोल) एस.एल.पी. स्नातकोत्तर महाविद्यायल, मुरार, ग्वालियर (म.प्र.) भारत

शोध सारांश – कृषि आधारित उद्योग सामान्यत: वे उद्योग होते हैं जिनका कृषि से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष संबंध होता है। इसमें कृषि कच्चे माल के साथ-साथ कृषि के आदानों के रूप में जाने वाली गतिविधियों और सेवाओं के आधार पर विभिन्न प्रकार की औद्योगिक, विनिमार्ण और प्रसंकरण गतिविधियों को शामिल किया गया हैं। ग्रामीण परिदृश्य में कृषि एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है इसलिए ग्रामीण विकास का आधार हैं कृषि आधारित उद्योग जो इस प्रमुख आर्थिक गतिविधि पर पनपते हैं, ग्रामीण विकास में भी एक महत्वपूर्ण पहलू हैं।

प्रस्तावना – ग्रामीण क्षेत्र को शहरी सुविधाओं के प्रावधान के माध्यम से गांवों का आर्थिक उत्थान एक महत्वपूर्ण विचार बन गया। इसमें कृषि और खाद्य प्रसंस्करण कृषि निर्माण इकाइयों के विकास, कृषि सेवा इकाई द्वारा ग्रामीण देश के सभी हिस्सों के लिए एक विश्वसनीय और गुणवत्तापूर्ण तरीके के बिजली का प्रवाधान ग्रामीण क्षेत्रों में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के सभी विस्तार के लिए शिक्षा और स्वास्थ शामिल है। परमाणु प्रोद्योगिकी, अंतरिक्ष और अवज्ञा प्रौद्योगिकी जैसे रणनीतिक क्षेत्रों का विकास राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास में इसके महत्व को देखते हुए वर्तमान अध्ययन सुक्ष्म स्तर का अध्ययन है। कृषि आधारित उद्योग ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अध्ययन में कृषि उत्पाद प्रसंस्करण इकाइयों कृषि-उत्पाद निमार्ण इकाइयों कृषि आदानों, विनिमार्ण इकाइयों और कृषि सेवा केंद्रों पर ध्यान केंद्रित किया गया था।

ग्रामीण विकास हेतु प्रसंस्करण उद्योग – प्रसंस्करण उद्योग उन गतिविधियों को संदर्भित करता है जो कृषि वस्तुओं को विभिन्न रूपों में परिवर्तित करते हैं जो उत्पाद में मूल्यों जोड़ते हैं। कृषि आधारित उद्योग वे उद्योग हैं जिनका कृषि से प्रत्यक्ष या अप्रयक्ष संबंध है। कृषि प्रसंस्करण उद्योग विशेष रूप से खाद्य निर्माण तंबाकू और कपड़ा प्रसंस्करण वाणिज्यिक औद्योगिक क्षेत्र पर हावी हैं। इस अर्थ में कृषि – प्रसंस्करण को एक समूह के रूप में परिभाषित किया गया है। कृषि उत्पादों के संरक्षण और संचालन के लिए और इसे भोजन ,चारा, फाइबर, ईंधन या औद्योगिक कच्चे माल के रूप में प्रयोग करने योग्य बनाने के लिए निम्नलिखित तकनीकी आर्थिक गतिविधियाँ आदि कृषि-प्रसंस्करण उद्योग गुंजाइश फसल से सभी कार्यों को शामिल करती हैं फसल के अंतिम चरण में सामग्री वांछित रूप मात्रा गुणावता और मूल्य में अंतिम उपयोगकर्ताओं तक पहुंचती हैं। प्राचीन भारतीय शास्त्र भोजन और औषधीय उपयोग के लिए कृषि उपज के संरक्षण का उल्लेख करते हैं और इसका विस्तृत विवरण है प्रसंस्करण के लिए कटाई के बाद और प्रसंस्करण प्रथाओं लेकिन अपर्याप्त ध्यान अतीत में कृषि-प्रसंस्करण क्षेत्र ने उत्पादक और उत्पादन दोनों को नुकसान पहुंचाया वही उपभोक्ता और इसने पर्यावरण को भी नुकासन पहुंचाया।

कृषि आधारित उद्योग परिर्माजन– कृषि एवं औद्योगिक विकास एक दूसरे के पूरक हैं कृषि के बिना उद्योग धन्धों का विकास नहीं हो सकता हैं और उद्योग धन्धों के बिना कृषि का समुन्नत विकास हो पाना असम्भव हैं। कृषि उद्योग धन्धों के बीच समन्वय होना आवश्यक है अध्ययन क्षेत्र की अर्थव्यवस्था कृषि नियोजन से सम्बन्धित महत्वपूर्ण कार्य किये है। वस्तुत: कृषि नियोजन सम्पूर्ण कृषि समुदाय को उत्पादन की ओर अग्रसर कर आर्थिक वृद्धि के एक उच्च दर को प्राप्त करने का प्रयास होता हैं। कृषि विकास योजना द्वारा भूमि की प्रत्येक इकाई के अनुकूलतम उपयोग को निर्धारित किया जाता है। इस उद्देश्य से नियोजन प्रक्रिया में आवश्यकतानुसार परिर्माजन एवं संशोधन की सुविधा के साथ ही समयानुसार बदलती परिथितियों के सन्दर्भ में उसमें परिवर्तन की सम्भावना बनी रहती है।

ग्रामीण विकास संकल्पना की वास्तविक रूपरेखा का अभ्युदय कब हुआ, इस संदर्भ में निश्चित एवं प्रामाणित रूप में कुछ कहना, करना कठिन प्रतीत होता है, फिर भी ऐसा विश्वास किया जाता है कि प्राचीन काल में क्षेत्र के विद्यमान संसाधनों के आर्थिक विकास हेतु प्रादेशिक नियोजन आमतौर पर एक उपागम के रूप में अपनाया जाता था। सामाजिक आर्थिक उन्नयन एवं संरचनात्मक परिवर्तन हेतु पूर्व नियोजन की प्रक्रिया एक अभिनव उपागम है जो मूलत: समाजवादी राष्ट्रों की देन है। भारत में योजनाबद्ध ग्रामीण विकास की शुरूआत वर्तमान सदी में ही की गयी। इसका प्रारम्भिक श्रेय रवीन्द्रनाथ टैगोर को जाता है जिन्होंने 1920 ई में शान्ति निकेतन के पास स्थित कुछ गांवों के विकास हेतु योजना बनाई। महात्मा गांधी ने इसे अधिक यथार्थवाद रूप प्रदान किया, जब उन्होंने ग्रामीणों के आपसी सहयोग और सद्भावना से ग्रामीण क्षेत्रों की विभिन्न समस्याओं और आर्थिक पिछड़ेपन को दूर करने का इस प्रयोजना में मेयर महोदय ने ग्रामीण नियोजन के कतिपय आधारभूत मुद्दों, अच्छा आवास विकसित परिवहन एवं संचार तंत्र ग्रामीण उत्पादो की नियमित और शीघ्र खपत, जल आपूर्ति एवं सिंचाई व्यवस्था और स्कूल, विकास हेतु कृषि कार्य, संचार शिक्षा स्वास्थ प्रशिक्षण समाज

कल्याण एवं गृह सम्बन्धी योजनाओं की समीक्षा प्रस्तुत की इसके बाद लाटन ने 1959 ई में ग्रामीण क्षेत्रों मे परिवर्तन में विभिन्न भौगोलिक तथ्यों पर तथा नाजियुत्त करीम 1967 ई समाज में व्याप्त कमियां जो आर्थिक सामाजिक उन्नयन में बाधक के नियन्त्रण पर बल दिया।

1967 ई में अल इण्डिया रूरल क्रेडिट रिफार्म कमेटी के सुझाव पर कृषिकों के तत्कालिक आवश्यकता एवं विकास के लिए लघु एवं सीमान्त तथा कृषि मजदूर विकास एजेन्सी गठित की गयी। इसके अन्तर्गत बैकों द्वारा भूमि विकास के लिए विभिन्न सुविधायों की गयी। ग्रामीण क्षेत्रों में व्यवसाय के अवसर बढाने हेतु तैयार की गयी नीतियों के अन्तर्गत आर्थिक वृद्धि कृषि का आधुनिकरण एवं ग्रामीण उद्योगों का विकास एवं ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के नये अवसर प्रदान करने का लक्ष्य रहा।

ग्रामीण विकास का केन्द्रीय लक्ष्य एक ऐसे विकास की प्रक्रिया का प्रारम्भ करता है जो लोगों के रहन-सहन के स्तर को उँचा उठा सके उनके लिए अधिक समूह और विभिन्नता पूर्ण जीवन की व्यवस्था कर सके। यह नियोजन तार्किक ढंग से भारतीय ग्रामीण विकास की विभिन्न समस्याओं का हल ढूंढता है, ग्रामीण के बीच व्याप्त आर्थिक और सामाजिक असमानताओं को दूर करता है। उपर्युक्त लक्ष्यों की प्राप्ति नियोजन के अभाव में सम्भव नहीं है। विभिन्न क्षेत्रों में विकास सम्बन्धी वरीयताएं रखी गयी है। यह नियोजन प्रजातांत्रिक ढंग से राजकीय निर्देशन में हो रहा हैं ग्रामीण विकास के सम्बन्ध में निम्न प्रविधियों का प्रयोग हुआ है संगठनात्मक संरचना में परिवर्तन मूल्य नीति के द्वारा साधनों का वितरण पूंजी संग्रह व साख व्यवस्था का विकास वित्तीय नीति का एक यंत्र के रूप में प्रयोग तथा विभिन्न विकास स्तरों पर नियंत्रण अकाल जांच आयोग ने कहा कि कृषि आधारित उद्योग वे है जो न केवल राज्य के औद्योगिकरण में सहायता करते हैं बल्कि खेतों के उत्पादों को संभालने के अलावा कृषि आदानों के साथ खेतों की आपूर्ति में भी शामिल है। नेशनल काउंसिल ऑफ एप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च 1965 ने कृषि आधारित उद्योग को परिभाषित किया करते हैं। इनमें बीज उर्वरक जरूरतों के लिए कृषि कच्चे माल उपयोग करते हैं इनमें केवल वस्तुएं शामिल हैं, बल्कि कृषि उपकरणों और मशीनरी की मरम्मत और सर्विसिंग भी शामिल है, कृषि आधारित उद्योगों को परिवर्तनकारी प्रक्रियाओं के विभिन्न स्तरों पर वर्गीकृत किया जा सकता है। सामान्य तौर पर पूंजी निवेश रूपांतरित तकनीकी जटिलता परिवर्तन की डिग्री के अनुपात में बढ़ जाती है। कच्चे माल या भोजन को बदलने का उद्देश्य प्रयोग करे योग्य रूप बनाना, भंडारण क्षमता को बढाना, अधिक आसानी से परिवहन योग्य रूप बनाना, और पौष्टिकता या पोषण गुणवत्ता को बढाना है।

ग्रामीण उद्योग की विशेषताऐ- कृषि आधारित उद्योग अपने कच्चे माल की तीन विशेषताओं के कारण अद्धितीय है- पहला-मौसमी, दूसरा-खराब होने, तीसरा-परिवर्तनशीलता।लेकिन सभी कृषि आधारित उद्योग इन विशेषताओं को समान रूप से साझा नहीं करते हैं।

कृषि उद्योगों में कच्चे माल की मात्रा और गुणवत्ता में परिवर्तनशीलता होती हैं मौसम में उतार-चढाव मिट्टी की स्थिति आदि के कारण मात्रा अनिशित है। मानवीकरण के कारण गुणवत्ता भिन्न होती हैं, कच्चे माल की मायावी बनी रहती है, भले ही पशु और पौधों के आनुवंशिकी में प्रगति हुई हो। विविधताएं उत्पादन शेडयूलिंग और गुणवत्ता नियंत्रण से संबंधित संचालन के संदर्भ में कृषि-औद्योगिक इकाइयों पर अतिरिक्त दबाव डालती है

ग्रामीण उद्योग का प्रसंस्करण- भारत में कृषि - प्रसंस्करण उद्योग आर्थिक विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और स्थानीय जरूरतों और निर्यात आवश्यकताओं को पूरा करने की क्षमता रखता हैं। सरकार द्वारा वित्त पोषित ग्रामीण विद्युतिकरण कार्यक्रम और सड़क और दूरसंचार नेटवर्क के माध्यम से बिजली आपूर्ति के मामले में इस उद्योग के लिए सहायक बुनियादी ढांचा अच्छी तरह से स्थापित है। ग्रामीण कारीगरों और उपयोगकर्ताओं के लिए विनिर्माण में अच्छी तरह से स्थापित कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम भी हैं। हालांकि इस क्षेत्र केा वर्तमान में राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के खराब प्रदर्शन स्थानिय और विदेशी वित्त दोनों सलाह, सीमित विपणन जानकारी और विश्वसनीय बाजारों की कमी से उत्पन्न कई चुनौतियों का सामान करना पड़ रहा है।

कृषि उद्योग कृषि उत्पादों जैसे कृषि फसलों वृक्ष फसलों, पशुधन और मत्स्य पालन के प्रसंस्करण में मदद करता है और उन्हें भोजन और अन्य उपयोगी रूपों में परिवर्तित करता हें निजी क्षेत्र को अभी तक कृषि उद्योग की पूरी क्षमता का एहसास नहीं हुआ है चीनी कॉफी चाय और प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ जैसे सॉस जेली, शहद आदि के लिए वैश्विक बाजार बहुत बड़ा है केवल आधुनिक तकनीक और गहन विपणन के साथ निर्यात बाजार का भी पूरा फायदा उठाया जा सकता है। इसलिए यह जरूरी है कि खाद्य निर्माता बदलती उपभोक्ता प्राथमिकताओं प्रौद्योगिकी आधुनिकरण नवाचार और कृषि - उत्पादन में नवीनतम रूझानों और प्रोद्योगिकी के समावेश को संपूर्ण खाद्य श्रृंखला के साथ समझें भारत और दुनिया में कृषि उत्पादों की कुल उत्पादन क्षमता अगला है। दशक तक दोगुना होने की संभावना है। इसके अलावा फल प्रसंस्करण मंत्रालय ने खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के कार्य योजना की स्थापना की थी। उद्देश्य खराब होने वाले खाद्य पदार्थ के प्रसंस्करण के स्तर को 6 प्रतिशत से बढकर 20 प्रतिशत मूल्यवर्धन को 20 प्रतिशत से 35 प्रतिशत से बढाकर 3 प्रतिशत और वैश्विक खाद्य व्यापार की हिस्सेदारी को 1.6 प्रतिशत से बढाकर 3 प्रतिशत करना है। कृषि में मशीनीकरण अथवा उन्नत आधुनिक क्रियाओं में बदल जायें यह मात्र एक दिन का कार्य नहीं हैं बल्कि दीर्घकालिक प्रक्रिया हैं। कृषि यंत्रीकरण में ट्रैक्टर सबसे महत्वपूर्ण कृषि - उद्योग में मुख्य रूप से मध्यवर्ती या अंतिम उपभोग के लिए कृषि उत्पादों के प्रसंस्करण और संरक्षण की कटाई के बाद की गतिविधियाँ शामिल हैं। यह दुनिया भर में एक अच्छी तरह से मान्यता प्राप्त तथ्य है, विशेष रूप से औद्योगिक विकास के संदर्भ में कृषि - उद्योगों का महत्व कृषि के सापेक्ष बढ़ता है क्योंकि अर्थव्यवस्थाएं विकसित होती हैं। इस बात पर जोर दिया जाना चाहिए कि भोजन केवल उत्पादन नहीं हैं। भोजन में प्रसंस्कृत उत्पादों की एक विस्तृत विविधता भी शामिल है। इस अर्थ में कृषि उद्योग विकाशील देशों में विनिमार्ण क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण और महत्वपूर्ण हिस्सा है और औद्योगिक क्षमता निर्माण का साधन हैं।

कृषि आधारित उद्योग की समस्याऐं - हर साल लाखों गरीब परिवार काम की तलाश में पलायन करते हैं। गांवों में आजीविका के धराशायी होने के कारण वे पलायन को मजबूर हैं ये संकटग्रस्त प्रवासी अक्सर अपने धरों को बंद कर लेते हैं, कुछ मामूली सामान ले जाते है और लंबी दूरी तय करते है अपने माता-पिता के साथ जाने वाले बच्चो को स्कूल छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ता हैं। 14 वर्ष से कम आयु के ऐसे बच्चों की संख्या लगभग 9 हर साल लाखों होने का अनुमान है। अपने गाँव से दूर होने के कारण वे उन जगहों से संबंधित नहीं होते हैं जहाँ वे जाते हैं और तेजी से अपने ही गाँवों में स्वीकृति खो देते हैं वे अपने समुदाय , संस्कृति और परंपराओं से अलग हो

गए है, त्यौहारों ,मेलों, धार्मिक और सामाजिक कार्यो में भाग लेने में असमर्थ हैं। जो उनके जीवन का एक अभिन्न अंग हैं और इस प्रकार उनकी पहचान की भावना खो देते हें। राज्य की सीमाओं को परा करने वाले लोगों की भेद्यता और भी अधिक है क्योंकि वे खुद को अपने ठेकेदारों पर अधिक से अधिक पाते हैं।

परंपरगत रूप से, किसान प्राकृतिक संसाधनों, श्रम कौशल और ज्ञान के साथ-साथ अपने निवेश का उपयोग करके या तो अपनी बात या वित्तीय ऋण से खाद्य और अन्य कृषि उत्पादों के उत्पादन होते हैं। लेकिन कुछ किसान दूसरों की तुलना में गरीब हैं। आमतौर पर वे भूमिहीन किसान होते हैं जिन्हें दूसरे लोगों की जमीन किराए पर देनी पड़ती है या दिहाड़ी मजदूर बन जाते हैं कृषि उत्पादों को आमतौर पर स्थानीय बिचौलिया या दलालों को निर्देशित किया जाता है, जो कभी-कभी बड़े राष्ट्रीय आपूर्तिकर्ताओं को वितरित करने से पहले किसानों को ऋण और बंधी हुई शर्तो के साथ उत्पादन के कारक प्रदान करते हैं। ये लोग फिर उत्पादों को बाजारों में बेचेगे। इस बाजारोन्मुखी ढांचे के तहत ज्यादतर किसान कीमत लेने वाले होते हैं। दुर्लभ परिस्थितियों को छोड़कर उनकी सौदेबाजी की शक्ति कम होती है जैसे कि बहुत जल्दी या देर से मौसम या उस अवधि के दौरान जहां आपूर्ति की कमी होती हैं। बाजार की मांग का जवाब देने की आवश्यकता है, लेकिन कोई सीधी पहुंच नहीं है, आसानी से खराब होने वाले उत्पादों से निपटना और ऋणी होना इस कम सौदेबाजी की शक्ति में योगदान करने वाले प्रमुख कारक है।

वर्तमान परिपेक्ष में- वर्तमान में कॉर्पोरेट ने उत्पादन पक्ष को नियंत्रित करने में एक प्रमुख हिस्सा ले लिया है। कॉर्पोरेट द्वारा कृषि आमतौर पर बड़े पैमाने पर और राष्ट्रीय बाजारों या बाहरी बाजारों तक सीधी बाजार पहुंच होती है। कई कॉरपोरेट को स्थानिय बिचौलियों द्वारा कृषि उत्पादों की आपूर्ति की जाती है जबकि अन्य का किसानों के साथ अनुबंध हो सकता है। मालिको और कारपोरेटों में काम करने वाले लोगों के लिए, कृषि सिर्फ एक आर्थिक क्षेत्र है और उनकी मूख्य चिंता उनकी आजीविका का एक अभिन्न अंग होने के बजाय हानि लाभ और वित्तीय लाभ के बारे में है। राष्ट्रीय या क्षेत्रीय स्तर पर कृषि की स्थिति के बारे में चर्चा करते समय आपूत्रि श्रृंखला में विभिन्न खिलाड़ियों, कॉर्पोरेट, बिचौलियों और छोटे और मध्यम किसानों के बीच अंतर करना चाहिए- ताकि उन पर प्रभाव और किसी विशेष स्थिति के प्रति उनकी प्रतिक्रिया को उनके संदर्भो के तहत स्पष्ट रूप से समझा जा सके। और वर्तमान बाजार संरचनाएं। समायोजन खाद्य आपूर्ति खाद्य मूल्य छोटे पैमाने पर कृषि उत्पादन व्यवसाय, लाभ आदि। संसाधन आधार जैसे। बीज, पानी, भूमि, जंगल, जैव विविधता आदि। कॉर्पोरेट कृषि मूल्य, जीवन का तरीका, संस्कृति संबंध, आय आदि।

निष्कर्ष- वर्तमान स्वरूप एवं ग्रामीण विकास के दृष्टिगत चयनित किया गया है वस्तुत: विभिन्न विद्धानों द्धारा विभिन्न क्षेत्रों के कृषि एवं औद्योगिक विकास विचार के विश्लेषण के लिए आन्तरिक एवं वाह्य गुणाकों को सम्मिलित किया जाता है। सूक्ष्म स्तरीय अध्ययन क्षेत्र के दृष्टिगत जिन विचारों का चयन किया गया हैं उनमें कृषि एवं विकास के विभिन्न पक्षों को समाहित करने का प्रयास किया गया हैं।

संदर्भ ग्रंथ सूची:-

1. विल्किसन और आर रोचा ,'द एग्रो-प्रोसेसिंग सेक्टर: अनुभवजन्य सारांश', हालिया
2. 'रुझान और विकास प्रभाव' , अंतर्राष्ट्रीय कृषि-उद्योग फोरम के लिए व्यापक पेपर , नई
3. दिल्ली ,अप्रैल 2008 ।
4. खाद्य और कृषि संगठन (एफएओ), वैश्विक संगठन ,'सामाजिक आर्थिक विकास और आर्थिक,स्थिति में कमी के लिए कृषि-व्यवसाय का महत्व', संपत्ति विकास पर विश्व संगठन आयोग केलिए चर्चा पत्र, सोलहवां सत्र, न्यूयॉर्क, मई, 5 - 16 , 2008.
5. ए.ओ. कमसंर, 'खाद्य निर्माण में सामग्री उत्पादकता', यांक जर्नल ऑफ एग्रीकल्चरल सोशलसाइंस, वॉल्यूम। 74, नंबर 1, फरवरी 1992, पीपी. 177-185।
6. आर.ई. लोपेज,'कनाडाई खाद्य प्रक्रिया उद्योग के भीतर आपूर्ति प्रतिक्रिया और निवेश', अमेरिकनजर्नल ऑफ एग्रीकल्चरल सोशल साइंस, वीओ। 67, नंबर 1, फरवरी , 1985, पीपी. 40-47
7. एस.एम. डाइट्ज़ और एस. मती, एसेसमेंट ऑफ़ द स्मॉल स्केल फूड प्रोसेस सब सेक्टर इनतंजानिया और अफ्रीकी राष्ट्र, आईएसबीएन , 2000।
8. Journal of the Association of North Indian Geographers Vol. 36, No. 1 June 2006,pp. 136.
9. Prakash Rao, V.L.S. (1963) Regional Planning Theoretical Approach, Calcutta, P. 5.
10. Kuklunski, A.K. (1978), Some Basic Issues in Regional Planning and NationalDevelopment in Mishra R.P. et. Al. (eds.) Vikas Publication, New Delhi, pp.5.
11. Mayer, A. and Associate (1959) : Pilot Project India the study of Rural Development ofEtawah, Uttar Pradesh Univ. of Calfornia Press, Berkeley and Los Angeles, 367.
12. Dubey, S.C. (1958) India's Changing Villages, Bombay.
13. Lawtan, G.H. (1958-59), India's Changing Villages, Royal Geographical SocietyofAustralia South Austrailian Branch paer (60), P. 17-24.

****